(c) and (d) Experience shows that losses are generally made good by subsequent additional efforts. Removal of infrastructural obstacles, wherever they occur, is an on-going process.

Setting up hundred per cent Export Oriented Units

750. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stress has been given to set up hundred per cent export oriented units by Government;

(b) if so, the number of such hundred per cent export oriented units which have been set up in Madhya Pradesh so far;

(c) the location of these units; and

(d) the details of proposal of Government regarding the establishment of hundred per cent export oriented units in Orissa during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Seven Export Oriented Units had reported commencement of production in the State of Madhya Pradesh as per details below:

Name of the Distt.	No. of units
Dhar	3
Raipur	2
Rajgarh	1
Raisen	1

These do not include units established under the Scheme but subsequently permitted debonding.

(d) Precise figures cannot be given as this would depend upon suitable project proposals emanating from Orissa.

डॉलर की दृष्टि से निर्यातों में गिरावट

751. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉलर की दृष्टि से पिछले दो वर्षों में किये गये निर्यात की तुलना में निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) डॉलर की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) निर्यातों में वर्ष 1990-91 की अपेक्षा 1991-92 के दौरान डालर के रूप में 1.5% की जो कमी आई थी, उसमें अप्रैल-दिसंबर, 92 में 1991-92 की उसी अवधि की तुलना में 3.41% की वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यातों में कमी भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन, विश्व व्यापार में मंदी, भुगतान संतुलन में संकट के कारण आयात में कमी किये जाने तथा अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण आई थी।

(ग) व्यापार नीति में जुलाई, 1991 में अनेक परिवर्तन किए गए थे जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसों में पर्याप्त कमी करना तथा आयात टैरिफ ढांचे को युक्तियुक्त बनाना है। विदेशी मुद्रा के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। इन्हें नई निर्यात-आयात नीति में और अधिक सुगठित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाना, उसका आधुनिकीकरण तथा प्रतियोगी क्षमता बढ़ाकर इसकी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। निर्यात गति में फिर से तेजी सुनिश्चित करने के लिए एक अल्पावधि कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, उप वस्तुओं को "अत्यधिक महत्व वाले" क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिसका उद्देश्य निर्यातों में प्रतिवर्ष मूल्य अथवा मात्रा के रूप में 30% की वृद्धि करना है।

(घ) 1989-90 से 1992-93 (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के लिए डालर के रूप में कुछ निर्यात निम्नानुसार है:—

(यू०एस० डालर मिलि०)

वर्ष	निर्यात
1989-90	16626
1990-91	18143
1991-92	17865
1992-93 (अप्रैल-दिसंबर)	13075
1991-92 (अप्रैल-दिसंबर)	12644

भारत के आयातों और निर्यातों पर डुंकेल प्रस्तावों का प्रभाव

752. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डुंकेल प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1986 को आधार-वर्ष के रूप में माना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान भारत की निर्यात और आयात स्थिति के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद भारत के आयात और निर्यात पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) डुंकेल दस्तावेज में कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता समाप्त करने संबंधी परिकलन के लिए आधार वर्ष 1986 से 1988 तक का औसत माना जाता है।

(ख) वर्ष 1986-89 के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख कृषि उत्पादकों द्वारा प्रतियोगी आर्थिक सहायता में कमी किये जाने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होगी जिससे भारत सहित उन देशों के लिए अवसर उत्पन्न होंगे जो कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं। जहां तक आयातों का संबंध है जब तक भारत की भुगतान संतुलन की समस्या है, तब तक आयात की मात्रा को नियंत्रित करना संभव रहेगा।

भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों के आयात

(करोड़ रु०)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
गेहूं	37.27	8.99	433.08
चावल	0.99	2.15	230.64
चीनी	205.24	193.07	0.13
खाद्य तेल	611.96	968.77	729.70
दाले	—	250.99	384.91
अपरिष्कृत ऊन	55.87	131.87	157.48

विवरण

भारत के प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात

(करोड़ रू०)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
चाय	576.78	601.18	609.41
काफी	296.70	261.55	293.52
चावल	197.33	338.60	331.44
मसाले	279.03	336.56	275.09
चीनी और शीरा	1.44	1.17	9.67
तम्बाकू अविनिर्मित	145.36	107.71	100.40

स्रोतः 1. एग्रीकल्चरल-स्टैटिस्टिक्स ऐट ग्लांस, कृषि मत्रांलय

2. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वाणिज्य मंत्रालय

Minimum Guarantee price for FCV Tobacco

753. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the minimum guarantee price fixed for F.C.V Tobacco;

(b) what is the manner in which its price is fixed; and

(c) what steps have been taken to implement the same?